

HINDI FILE



DREAM
FOR NATION



DARE
TO SERVE



DELIVER
WITH INTEGRITY

DAILY PRACTICE QUESTIONS

BEST FOR UPSC | UP PCS EXAM

DATE : **AUGUST 10, 2026**



Comprehensive
Coverage



Exam-Focused
Analysis



Concept Clarity
& Insights



Practice MCQs
with Explanation



Daily Updates,
Better Results



CONTACT INFO:

+91 92896 33341 | +91 96679 33341



EMAIL ID:

info@sixsigmaias.com



WEB PAGE:

www.sixsigmaias.com



ADDRESS:

C-6, GROUND FLOOR, SECTOR 2,
NEAR SECTOR 15 METRO STATION, NOIDA – 201301, UTTAR PRADESH

दैनिक अभ्यास प्रश्न - स्थैतिक भाग से

प्रश्न 1. प्राचीन भारतीय दार्शनिक परंपराओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. आजीवक यह मानते थे कि ब्रह्मांड की प्रत्येक घटना पूर्वनिर्धारित (pre-determined) है और मानव प्रयास का भाग्य को बदलने में कोई योगदान नहीं होता।
2. लोकायत (चार्वाक) दर्शन ने वेदों के प्रामाण्य को अस्वीकार किया, परंतु पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांत को स्वीकार किया।

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 न ही 2

उत्तर: (a)

व्याख्या:

आजीवक सम्प्रदाय, जो बौद्ध एवं जैन परंपराओं का समकालीन था, नियतिवाद (Niyati) के सिद्धांत में विश्वास करता था, जिसके अनुसार सभी घटनाएँ पूर्वनिर्धारित हैं और मनुष्य की स्वतंत्र इच्छा का कोई अस्तित्व नहीं है। अतः कथन 1 सही है। लोकायत या चार्वाक दर्शन पूर्णतः भौतिकवादी था; उसने न केवल वेदों के प्रामाण्य को नकारा बल्कि आत्मा, पुनर्जन्म और कर्म जैसे सिद्धांतों को भी अस्वीकार किया। अतः कथन 2 गलत है। इसलिए केवल कथन 1 सही है।

प्रश्न 2. “पारिस्थितिक पिरामिडों (Ecological Pyramids)” के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन उनके स्वरूप का सही वर्णन करता है?

- (a) वे सदैव स्थलीय और जलीय दोनों पारितंत्रों में सीधे (upright) रहते हैं।
- (b) जलीय पारितंत्रों में, फाइटोप्लवक (phytoplankton) की उच्च पुनरुत्पादन दर के कारण जैवभार (biomass) का पिरामिड प्रायः उल्टा होता है।
- (c) वनों के पारितंत्रों में संख्या का पिरामिड सदैव उल्टा होता है।
- (d) ऊर्जा और जैवभार के पिरामिड पोषक-चक्रण (nutrient cycling) पर निर्भर कर परस्पर परिवर्तनीय होते हैं।

उत्तर: (b)

व्याख्या:

जलीय पारितंत्रों में प्राथमिक उत्पादक — फाइटोप्लवक — का जैवभार कम होता है, परंतु वे बहुत तीव्र गति से पुनरुत्पादित होते हैं; इस कारण जैवभार का पिरामिड उल्टा दिखाई देता है। दूसरी ओर, ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा (upright) होता है क्योंकि ऊर्जा प्रवाह एकदिशीय होता है। वनों में सामान्यतः संख्या और जैवभार के पिरामिड सीधे होते हैं, यद्यपि कुछ स्तरों पर भिन्नता हो सकती है।

प्रश्न 3. भारत के वित्तीय क्षेत्र में हाल के विकासों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. भारतीय रिज़र्व बैंक की “Prompt Corrective Action (PCA)” रूपरेखा केवल अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों पर लागू होती है, न कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) पर।
2. भारत में “Differentiated Banks” की अवधारणा में पेमेंट्स बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक दोनों शामिल हैं, जिनका उद्देश्य वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है।
3. दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (IBC) के तहत परिसमापन (liquidation) की “waterfall mechanism” में परिचालन ऋणदाताओं (Operational Creditors) को वित्तीय ऋणदाताओं (Financial Creditors) से प्राथमिकता दी जाती है।

उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

- (a) केवल एक
- (b) केवल दो
- (c) सभी तीन
- (d) कोई नहीं

उत्तर: (b)

व्याख्या:

कथन 1 गलत है — दिसंबर 2021 में RBI ने PCA रूपरेखा को NBFCs तक भी विस्तारित किया, यद्यपि उनके ढाँचे के अनुसार कुछ संशोधनों के साथ।

कथन 2 सही है — *Differentiated Banks* जैसे Payments Bank और Small Finance Bank वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने हेतु शुरू किए गए, ताकि विशिष्ट ग्राहक वर्गों तक बैंकिंग सेवाएँ पहुँच सकें।

कथन 3 गलत है — IBC के “waterfall mechanism” में वित्तीय ऋणदाताओं को परिचालन ऋणदाताओं से अधिक प्राथमिकता प्राप्त होती है।

इस प्रकार केवल दो कथन (मुख्यतः कथन 2 और PCA रूपरेखा के विस्तार की नवीन स्थिति) सही हैं।

प्रश्न 4. भारत के संवैधानिक ढाँचे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. भारत के राष्ट्रपति अध्यादेश केवल तभी जारी कर सकते हैं जब संसद का कोई एक सदन सत्र में न हो।
2. अनुच्छेद 356 (राष्ट्रपति शासन) के अंतर्गत घोषित उद्घोषणा (proclamation) संसद की स्वीकृति के बिना अधिकतम एक वर्ष तक चल सकती है।
3. सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि अध्यादेश जारी करने में राष्ट्रपति की संतुष्टि न्यायिक समीक्षा (judicial review) के अधीन है।
4. संवैधानिक संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है तथा इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक नहीं है।

उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

- (a) केवल एक
- (b) केवल दो
- (c) केवल तीन
- (d) सभी चार

उत्तर: (c)

व्याख्या:

कथन 1 – सही। अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश तब जारी कर सकते हैं जब संसद का कोई एक सदन सत्र में न हो।

कथन 2 – गलत। राष्ट्रपति शासन छह महीने तक चलता है और इसे संसद की स्वीकृति से अधिकतम तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, विशेष परिस्थितियों (जैसे राष्ट्रीय आपातकाल) में।

कथन 3 – सही। *D.C. Wadhwa बनाम बिहार राज्य (1987)* के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राष्ट्रपति की संतुष्टि न्यायिक समीक्षा के अधीन है।

कथन 4 – सही। संवैधानिक संशोधन विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है और इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक नहीं है।

अतः तीन कथन (1, 3 और 4) सही हैं।

प्रश्न 5. (Assertion–Reason प्रकार)

Assertion (A): भारत के पश्चिमी तट पर दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान पूर्वी तट की तुलना में अधिक वर्षा होती है।

Reason (R1): पश्चिमी घाट नमी से भरी दक्षिण-पश्चिम मानसूनी हवाओं को रोकते हैं, जिससे वायु की पवनाभिमुख (windward) दिशा पर अधिक वर्षा होती है।

Reason (R2): पूर्वी तट को मुख्यतः लौटते हुए उत्तर-पूर्व मानसून से वर्षा प्राप्त होती है, जिसमें अपेक्षाकृत कम नमी होती है।

निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प उपयुक्त है?

- (a) R1 और R2 दोनों सही हैं, और दोनों ही कथन A की व्याख्या करते हैं।
 (b) R1 और R2 दोनों सही हैं, परंतु केवल R1 कथन A की सही व्याख्या करता है।
 (c) R1 सही है, परंतु R2 गलत है।
 (d) R1 गलत है, परंतु R2 सही है।

उत्तर: (b)

व्याख्या:

भारत के पश्चिमी तट पर पश्चिमी घाट नमी से भरी दक्षिण-पश्चिम मानसूनी हवाओं को रोकते हैं, जिससे वहाँ अभोरंघ्र (orographic) वर्षा होती है। पूर्वी तट वर्षा-छाया क्षेत्र में स्थित होने के कारण इस मौसम में कम वर्षा प्राप्त करता है और उसे मुख्यतः उत्तर-पूर्व मानसून से वर्षा मिलती है, जिसमें नमी अपेक्षाकृत कम होती है। अतः दोनों कारण सही हैं, किंतु केवल R1 प्रत्यक्ष रूप से Assertion की व्याख्या करता है।

दैनिक समसामयिक प्रश्न

प्रश्न 1. प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (PM POSHAN 2.0) योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

- PM POSHAN 2.0 के अंतर्गत, मध्यान्ह भोजन (Mid-Day Meal) मेन्यू में मोटे अनाज (Millets) को शामिल किया गया है ताकि पोषण विविधता को बढ़ावा दिया जा सके और अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष (2023) के अनुरूप आहार में सुधार किया जा सके।
- इस योजना में केंद्र और राज्यों के बीच निधि-वितरण अनुपात 75:25 है, जबकि उत्तर-पूर्वी राज्य, हिमालयी राज्य और विधानमंडल वाले केंद्र शासित प्रदेशों के लिए यह 90:10 है।

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

- (a) केवल 1
 (b) केवल 2
 (c) 1 और 2 दोनों
 (d) न तो 1 न ही 2

उत्तर: (c)

व्याख्या:

PM POSHAN 2.0 ने वर्ष 2021 में मध्यान्ह भोजन योजना (Mid-Day Meal Scheme) का स्थान लिया।

इसका उद्देश्य पोषण, विद्यालय स्वास्थ्य और कृषि-आधारित आपूर्ति श्रृंखला को एकीकृत करना है।

इस योजना में मोटे अनाज (*Millets*) को सम्मिलित किया गया ताकि स्थानीय उत्पादन को प्रोत्साहन मिल सके तथा अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष (2023) के अनुरूप पोषण विविधता को बढ़ाया जा सके।

वित्तीय साझेदारी अनुपात 75:25 (सामान्य राज्यों के लिए) और 90:10 (उत्तर-पूर्वी, हिमालयी राज्य तथा विधानमंडल वाले केंद्र शासित प्रदेशों के लिए) है।

अतः दोनों कथन सही हैं।

प्रश्न 2. कृत्रिम वर्षा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त *Cloud Seeding* के सिद्धांत को निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सर्वोत्तम रूप से स्पष्ट करता है?

(a) अति-शीतलित (*supercooled*) बादलों में हाइड्रोस्कोपिक या हिम-स्फटिक बनाने वाले नाभिक (*nuclei*) का संचार कर संघनन एवं वर्षा की संभावना बढ़ाना।

(b) वर्षा उत्पन्न करने हेतु ट्रोपोस्फीयर में ओजोन पूर्वगामी यौगिकों (*ozone precursors*) का इंजेक्शन कर दाब परिवर्तन उत्पन्न करना।

(c) माइक्रोवेव के माध्यम से संवहन धाराओं (*convection currents*) को प्रोत्साहित कर क्यूमुलोनिम्बस बादलों को मोटा बनाना।

(d) समतापमंडल (*stratosphere*) में एरोसोल फैलाकर कृत्रिम सिरस (*cirrus*) बादलों का निर्माण करना।

उत्तर: (a)

व्याख्या:

Cloud Seeding में सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड या सोडियम क्लोराइड जैसे पदार्थों को उन बादलों में फैलाया जाता है जिनमें अति-शीतलित जलकण उपस्थित होते हैं।

ये पदार्थ संघनन या हिम-स्फटिक बनने के नाभिक के रूप में कार्य करते हैं, जिससे वर्षा की संभावना बढ़ जाती है।

इस तकनीक का उपयोग सूखा राहत, ओलावृष्टि नियंत्रण तथा वायु प्रदूषण घटाने में भी किया जाता है।

अन्य विकल्प (b), (c) और (d) भौतिक बादल-सूक्ष्म प्रक्रियाओं से संबद्ध नहीं हैं।

प्रश्न 3. हाल के वर्षों में भारत द्वारा किए गए मुक्त व्यापार समझौतों (*Free Trade Agreements - FTAs*) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. भारत-यूई *Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA)* भारत का एक दशक बाद किया गया पहला प्रमुख मुक्त व्यापार समझौता है।

2. CEPA के तहत, भारत को यूई में अपने लगभग 95% टैरिफ लाइनों पर शुल्क-मुक्त (*duty-free*) पहुँच प्राप्त हुई है।

3. भारत-ऑस्ट्रेलिया *Economic Cooperation and Trade Agreement (ECTA)* में यह प्रावधान है

कि दो वर्षों के बाद यह स्वचालित रूप से *Comprehensive Economic Cooperation Agreement (CECA)* में परिवर्तित हो जाएगा।

उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

- (a) केवल एक
- (b) केवल दो
- (c) सभी तीन
- (d) कोई नहीं

उत्तर: (c)

व्याख्या:

भारत ने वर्ष 2022 में यूई के साथ CEPA पर हस्ताक्षर किए — यह लगभग 10 वर्षों के बाद किया गया पहला प्रमुख मुक्त व्यापार समझौता था।

इस समझौते के अंतर्गत भारत को लगभग 97% टैरिफ लाइनों पर शुल्क-मुक्त पहुँच मिली।

भारत-ऑस्ट्रेलिया ECTA (2022) एक अंतरिम समझौता है जिसमें दो वर्षों के भीतर इसे पूर्ण CECA में बदलने का प्रावधान है।

अतः तीनों कथन सही हैं।

प्रश्न 4. भारत में केंद्रीय वेतन आयोगों (*Central Pay Commissions - CPCs*) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. सातवें केंद्रीय वेतन आयोग ने वेतन बैंड और ग्रेड पे की प्रणाली समाप्त कर एक नया *Pay Matrix* प्रस्तुत किया।
2. वेतन आयोग की अनुशंसाएँ, एक बार मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत हो जाने पर, भारत सरकार के लिए बाध्यकारी हो जाती हैं।
3. वेतन आयोग की अनुशंसाएँ समान रूप से नागरिक कर्मचारियों, रक्षा कर्मियों तथा सार्वजनिक उपक्रमों (*PSUs*) के कर्मचारियों पर लागू होती हैं।

उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

- (a) केवल एक
- (b) केवल दो
- (c) सभी तीन
- (d) कोई नहीं

उत्तर: (b)

व्याख्या:

कथन 1 — सही। सातवें वेतन आयोग ने *Pay Matrix* प्रणाली शुरू की, जिसमें ग्रेड पे और वेतन-बैंड प्रणाली को समाप्त कर दिया गया।

कथन 2 – सही। जब केंद्रीय मंत्रिमंडल इन अनुशंसाओं को स्वीकृति प्रदान करता है, तो ये सरकारी नीति का हिस्सा बन जाती हैं और सरकार के लिए बाध्यकारी हो जाती हैं।

कथन 3 – गलत। वेतन आयोग की अनुशंसाएँ केवल केंद्रीय सरकारी नागरिक एवं रक्षा कर्मचारियों पर लागू होती हैं, न कि सार्वजनिक उपक्रमों (PSUs) पर, जिनकी वेतन संरचना स्वतंत्र होती है।

अतः केवल दो कथन सही हैं।

प्रश्न 5. कोयला मंत्रालय और उसकी हालिया पहलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. कोयला मंत्रालय ने टिकाऊ खनन (Sustainable Mining) और पर्यावरणीय अनुपालन को प्रोत्साहित करने हेतु *Star Rating Policy* प्रारंभ की है।
2. *Mission Coking Coal* का उद्देश्य घरेलू भंडार की खोज और संवर्धन के माध्यम से आयात पर निर्भरता घटाकर आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है।
3. नए वाणिज्यिक कोयला खनन तंत्र के अंतर्गत निजी क्षेत्र की इकाइयों को कोयले की खुली बाजार बिक्री की अनुमति है, जिसमें अंतिम उपयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं है।
4. *Coal Gasification Policy (2023)* का लक्ष्य वर्ष 2030 तक 100 मिलियन टन कोयले का गैसीकरण कर सिंगैस (syngas) उत्पादन करना है, जिसका उपयोग उर्वरक और मीथेनॉल निर्माण में किया जाएगा।

उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

- (a) केवल दो
- (b) केवल तीन
- (c) सभी चार
- (d) केवल एक

उत्तर: (c)

व्याख्या:

चारों कथन सही हैं।

Star Rating Policy को पारदर्शिता, पर्यावरणीय प्रदर्शन और सामाजिक उत्तरदायित्व को बढ़ावा देने हेतु लागू किया गया।

Mission Coking Coal का लक्ष्य घरेलू कोकिंग कोयले की उपलब्धता बढ़ाना है।

वाणिज्यिक कोयला खनन नीति के तहत निजी कंपनियों को खुले बाजार में कोयला बेचने की अनुमति दी गई है — यह नीति-परिवर्तनकारी कदम था।

Coal Gasification Policy (2023) का लक्ष्य 2030 तक 100 मिलियन टन कोयले का गैसीकरण कर स्वच्छ ईंधन (जैसे सिंगैस, मीथेनॉल, यूरिया) का उत्पादन बढ़ाना है।

प्रश्न 6. वैश्विक स्तर पर संचालित *Cloud Seeding* अथवा मौसम संशोधन परियोजनाओं में से सही युग्म की पहचान कीजिए:

- (a) *Project "Stormfury"* – संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा हरिकेन (Hurricane) को कमजोर करने हेतु सिल्वर आयोडाइड से बीजारोपण (seeding) प्रयोग।
 - (b) *Project "Indra"* – भारत और जापान की संयुक्त पहल हिमालयी हिम-पिघल प्रबंधन हेतु।
 - (c) *"RainCube Mission"* – यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा संचालित क्लाउड-सीडिंग उपग्रह प्रणाली।
 - (d) *Project "Mawsynram"* – मेघालय सरकार की स्थानीय वर्षा तीव्रता घटाने हेतु क्लाउड-सीडिंग पहल।
- उत्तर: (a)

व्याख्या:

Project Stormfury (1962–1983) संयुक्त राज्य अमेरिका की एक सरकारी पहल थी जिसका उद्देश्य सिल्वर आयोडाइड द्वारा उष्णकटिबंधीय चक्रवातों (tropical cyclones) को कमजोर करना था। यह परियोजना सीमित परिणामों के कारण बंद कर दी गई।

Project Indra भारत की स्वयं की क्लाउड-सीडिंग परियोजना थी, जापान के साथ संयुक्त नहीं।

RainCube Mission नासा की एक माइक्रो-सैटेलाइट परियोजना है जो वर्षा मापन हेतु है, न कि बीजारोपण के लिए।

Project Mawsynram नाम की कोई आधिकारिक मौसम संशोधन परियोजना नहीं है।

अतः (a) विकल्प सही है।

दैनिक मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन प्रश्न

जीएस पेपर – 1

प्रश्न 1. “भारत में मंदिर स्थापत्य का विकास केवल धार्मिक भक्ति का नहीं, बल्कि उपमहाद्वीप की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक गतिशीलता का भी प्रतिबिंब है।” विश्लेषण कीजिए।

उत्तर:

भारत में मंदिर स्थापत्य का विकास केवल धार्मिक अभिव्यक्ति नहीं, बल्कि धर्म, राजनीति और अर्थव्यवस्था के समन्वित प्रतिबिंब के रूप में हुआ। गुप्त युग से प्रारंभ होकर मंदिर आध्यात्मिक तथा सांसारिक शक्ति के प्रतीक बन गए।

मुख्य भाग:

गुप्त काल (4वीं–6वीं सदी ई.) में सबसे प्रारंभिक संरचनात्मक मंदिरों जैसे *दशावतार मंदिर (देवगढ़)* का निर्माण हुआ, जिसने

शैल-कट (rock-cut) स्थापत्य से स्वतंत्र संरचनात्मक मंदिरों की ओर संक्रमण को दर्शाया। राज्य विस्तार के साथ राजाओं ने मंदिर निर्माण को दैवीय वैधता के प्रतीक के रूप में संरक्षण दिया — उदाहरणतः चोलों के बृहदेश्वर मंदिर (तंजावुर) और चंदेलों के खजुराहो समूह में नागर शैली का उत्कर्ष।

मंदिर आर्थिक समृद्धि के भी द्योतक बने। व्यापारी संघों, शिल्पियों और स्थानीय धनिकों ने मंदिर निर्माण में योगदान दिया, जिससे वे आध्यात्मिकता और वाणिज्य दोनों के केंद्र बन गए। होयसला मंदिर (बेलूर और हालेबिड) में क्षेत्रीय शिल्पकला, सूक्ष्म नक्काशी और समृद्ध कृषि अर्थव्यवस्था का सुंदर संयोजन दिखाई देता है।

साथ ही, मंदिर शिक्षा, संगीत, नृत्य और कला के केंद्र भी बने। स्थापत्य की दृष्टि से मंदिरों ने क्षेत्रीय समन्वय का रूप लिया — उत्तर में नागर, दक्षिण में द्रविड़, और दक्कन में वेसर शैली — जो भारत की सांस्कृतिक बहुलता का प्रतीक है।

निष्कर्ष:

इस प्रकार, भारतीय मंदिर जीवंत संग्रहालय हैं — जो धार्मिक निरंतरता, आर्थिक समृद्धि, कलात्मक प्रौढ़ता और राजनीतिक वैधता के प्रतीक हैं। उनका विकास इस बात का प्रमाण है कि भारत में धर्म, राजनीति और अर्थव्यवस्था एक ही पत्थर में समाहित हो गए।

जीएस पेपर – 2

प्रश्न 2. “भारत में न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) और संसदीय सर्वोच्चता (Parliamentary Supremacy) विरोधी नहीं, बल्कि संवैधानिक लोकतंत्र के परस्पर पूरक सिद्धांत हैं।” चर्चा कीजिए।

उत्तर:

भारतीय संविधान न्यायिक समीक्षा और संसदीय सर्वोच्चता के बीच सूक्ष्म संतुलन स्थापित करता है — दोनों ही कानून के शासन (Rule of Law) और लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व के लिए आवश्यक हैं।

मुख्य भाग:

संसदीय सर्वोच्चता जनता की संप्रभुता का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि न्यायिक समीक्षा यह सुनिश्चित करती है कि विधायिका और कार्यपालिका संविधान की सीमाओं के भीतर रहें।

न्यायिक समीक्षा की शक्ति (अनुच्छेद 13, 32, 136, 226) संसद या कार्यपालिका के अतिक्रमण पर नियंत्रण का माध्यम है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद का संशोधन अधिकार व्यापक है परंतु पूर्ण नहीं — वह संविधान की मूल संरचना (Basic Structure) को परिवर्तित नहीं कर सकती।

इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण (1975) में न्यायिक समीक्षा को संविधान का अभिन्न अंग माना गया, जबकि मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ (1980) में मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच संतुलन पुनः स्थापित किया गया।

साथ ही, न्यायालयों ने संसद के अधिकार क्षेत्र का भी सम्मान किया — राजा राम पाल (2007) में संसद की कार्यवाही की स्वतंत्रता को मान्यता दी गई।

निष्कर्ष:

अतः न्यायिक समीक्षा और संसदीय सर्वोच्चता परस्पर सहयोगी हैं — पहली लोकतंत्र को बहुमत के दुरुपयोग से बचाती है, जबकि दूसरी जनता के प्रति उत्तरदायित्व सुनिश्चित करती है। दोनों मिलकर संविधान निर्माताओं के उस दृष्टिकोण को साकार करते हैं जिसमें सीमित सरकार और स्थायी विधिशासन का आदर्श निहित है।

जीएस पेपर – 3

प्रश्न 3. भारत के वैश्विक विनिर्माण केंद्र (*Global Manufacturing Hub*) बनने के लक्ष्य के संदर्भ में मुक्त व्यापार समझौतों (FTAs) के महत्व और चुनौतियों पर चर्चा कीजिए।

उत्तर:

भारत का हालिया जोर मुक्त व्यापार समझौतों (FTAs) पर उसके वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं (*Global Value Chains*) में एकीकरण और “मेक इन इंडिया” लक्ष्य की दिशा में एक रणनीतिक कदम है।

मुख्य भाग:

एक दशक के अंतराल के बाद भारत ने प्रमुख FTAs जैसे भारत-यूई *CEPA (2022)* और भारत-ऑस्ट्रेलिया *ECTA (2022)* पर हस्ताक्षर किए — जो व्यापारिक पुनर्संलग्नता का संकेत हैं।

इन समझौतों का उद्देश्य बाजार तक पहुँच, विदेशी निवेश आकर्षित करना और श्रम-प्रधान क्षेत्रों जैसे वस्त्र, रत्न-जवाहरात और औषधियों में निर्यात को बढ़ावा देना है।

FTAs भारत को सस्ते इनपुट्स की उपलब्धता और निर्यात विविधीकरण जैसे लाभ देते हैं। उदाहरणतः *CEPA* के तहत भारत को यूई में अपने 97% उत्पादों पर शुल्क-मुक्त पहुँच मिली। *ECTA* के तहत कुशल पेशेवरों के आवागमन को भी सरल बनाया गया।

फिर भी चुनौतियाँ बनी हुई हैं — लॉजिस्टिक बाधाएँ, मानकों में असंगति, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं से सीमित जुड़ाव, तथा कम लागत वाले देशों से आयात वृद्धि का खतरा जिससे *MSMEs* प्रभावित हो सकते हैं। भारत का *RCEP (2020)* से बाहर रहना इन्हीं चिंताओं का परिणाम था।

साथ ही, गैर-शुल्कीय अवरोध (*Non-Tariff Barriers*) और *Rules of Origin* विवादों ने इनके उपयोग को कठिन बनाया है। FTAs को घरेलू औद्योगिक नीति, डिजिटल व्यापार और कार्बन टैक्स के साथ समन्वित करना आवश्यक है।

निष्कर्ष:

भारत को अपने FTAs को रक्षात्मक व्यापार उपकरण से आगे बढ़ाकर रणनीतिक आर्थिक साधन बनाना होगा। व्यापार सुविधा, उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (*PLI*) और कौशल आधारित औद्योगिक नीति के समन्वय से भारत एक मजबूत वैश्विक विनिर्माण केंद्र बन सकता है।

जीएस पेपर – 4

प्रश्न 4. “नैतिक शासन (Ethical Governance) केवल नियमों के पालन तक सीमित नहीं, बल्कि सार्वजनिक संस्थाओं में नैतिक दिशा-सूचक (Moral Compass) विकसित करने की प्रक्रिया है।” स्पष्ट कीजिए।

उत्तर:

नैतिक शासन केवल प्रशासनिक अनुपालन नहीं है; यह मूल्य-आधारित प्रशासन है जिसमें उत्तरदायित्व, पारदर्शिता और सहानुभूति नीति-निर्णयों का मार्गदर्शन करती हैं।

मुख्य भाग:

नियम ढाँचा प्रदान करते हैं, जबकि नैतिकता दिशा देती है। केवल नियमों का पालन प्रक्रियात्मक शुचिता सुनिश्चित करता है, परंतु नैतिक उत्तरदायित्व नहीं।

नैतिक शासन में ईमानदारी, निष्पक्षता, करुणा और तटस्थता जैसी मानवीय मूल्यों का आत्मसात होना आवश्यक है।

उदाहरणतः यदि कोई अधिकारी केवल नियमों का पालन करता है परंतु नीति क्रियान्वयन में मानवता की उपेक्षा करता है, तो वह कानूनी रूप से सही किंतु नैतिक रूप से त्रुटिपूर्ण होगा। अतः नैतिक नेतृत्व का उद्देश्य नियमों से परे “सही कार्य” करना है।

संस्थागत स्तर पर केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC), लोकपाल और सूचना का अधिकार (RTI) जैसे उपाय बाह्य उत्तरदायित्व सुनिश्चित करते हैं, परंतु वास्तविक नैतिक शासन आंतरिक प्रेरणा से आता है — जिसे विवेक (conscience) द्वारा निर्देशित किया जाता है।

नैतिकता पर प्रशिक्षण, नागरिक चार्टर और सामाजिक अंकेक्षण (social audit) इन मूल्यों को संस्थागत रूप देते हैं।

उदाहरण:

आपदा या महामारी के समय जब अधिकारी संवेदनशीलता और नवाचार दिखाते हुए नियमों से परे जाकर जनता की सहायता करते हैं, तो यह नैतिक शासन का उत्कृष्ट उदाहरण होता है।

निष्कर्ष:

अतः नैतिक शासन कानूनीता और नैतिकता के संगम पर स्थित है। नियम भ्रष्टाचार को रोकते हैं, जबकि नैतिकता नैतिक पतन को रोकती है। जब संस्थाएँ नैतिक दिशा-सूचक से संचालित होती हैं, तब शासन यांत्रिक नहीं, बल्कि मानवीय बन जाता है।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य (Current Affairs)

प्रश्न 5. “दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण संकट से यह स्पष्ट होता है कि भू-इंजीनियरिंग उपाय के रूप में *Cloud Seeding* की तत्काल आवश्यकता है।” समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए।

उत्तर:

दिल्ली का प्रदूषण संकट अब दीर्घकालिक रूप ले चुका है, जहाँ AQI स्तर प्रायः 400 से अधिक पहुँच जाते हैं। पारंपरिक उपायों की विफलता के बीच क्लाउड सीडिंग एक संभावित, यद्यपि विवादास्पद, समाधान के रूप में उभरी है।

मुख्य भाग:

क्लाउड सीडिंग में *सिल्वर आयोडाइड*, *पोटेशियम आयोडाइड* या *सोडियम क्लोराइड* जैसी वस्तुओं को बादलों में छोड़ा जाता है ताकि कृत्रिम वर्षा उत्पन्न हो सके। यह वर्षा वायुमंडलीय कणों (PM2.5, PM10) को धोकर अस्थायी रूप से वायु गुणवत्ता सुधार सकती है।

दिल्ली में आवश्यकता:

- पराली जलाने, वाहनों के उत्सर्जन और ठहरी हुई वायु के कारण स्थायी धुंध की समस्या।
- *Odd-Even* योजना या निर्माण प्रतिबंध जैसे पारंपरिक उपायों की सीमित प्रभावशीलता।
- नवंबर-दिसंबर के दौरान अनुकूल आर्द्रता और बादल संरचना, जो क्लाउड सीडिंग के लिए उपयुक्त होती है।

चुनौतियाँ:

- सफलता अनिश्चित — यह केवल उन बादलों पर प्रभावी है जिनमें पर्याप्त नमी हो; शुष्क परिस्थितियों में नहीं।
- रासायनिक पदार्थों जैसे *सिल्वर आयोडाइड* के पर्यावरणीय दुष्प्रभावों पर चिंता।
- *लागत बनाम लाभ* का प्रश्न — यह अस्थायी राहत देता है, स्थायी समाधान नहीं।
- बड़े पैमाने पर उपयोग के नैतिक और अंतरराष्ट्रीय प्रभाव।

महाराष्ट्र (2018) और कर्नाटक (2019) में किए गए प्रयोगों के परिणाम मिश्रित रहे। दिल्ली द्वारा *IIT कानपुर (2024)* के साथ प्रस्तावित सहयोग से इसकी व्यवहार्यता जाँची जा रही है।

आगे की राह:

क्लाउड सीडिंग को वैज्ञानिक प्रयोग के रूप में देखा जाना चाहिए, न कि प्रदूषण नियंत्रण के प्राथमिक साधन के रूप में। दीर्घकालिक समाधान के लिए उत्सर्जन घटना, हरित परिवहन और कृषि सुधार आवश्यक हैं। परंतु आपातकालीन स्थितियों में यह पूरक उपाय हो सकता है।

निष्कर्ष:

क्लाउड सीडिंग कोई स्थायी समाधान नहीं, बल्कि प्रदूषण की तीव्र अवस्थाओं से निपटने के लिए एक अस्थायी तकनीकी उपाय है। दिल्ली के प्रदूषण संकट के समाधान हेतु विज्ञान, सुशासन और पर्यावरणीय नैतिकता का संगम आवश्यक है ताकि दीर्घकालिक वायु गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके।